

प्रेषक,

आर०के०तोमर,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून दिनांक 15 फरवरी 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-27 के अंतर्गत राज्य सेक्टर की आयोजनागत पक्ष की योजना "वनों की सुरक्षा" हेतु राजस्व लेखा में द्वितीय किस्त का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन उत्तराखण्ड के पत्र सं० नि०-1364/3-5(रा०सै०-वनों की सुरक्षा) दिनांक 18.01.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान सं०-27 के अंतर्गत राज्य सेक्टर की आयोजनागत पक्ष की योजना "वनों की सुरक्षा" हेतु पूर्व में अवमुक्त ₹72.00 लाख के अतिरिक्त वर्तमान में निम्न विवरणानुसार ₹72.00 लाख (सبعहत्तर लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

अनुदान संख्या-27 (राजस्व लेखा)

आयोजनागत

(धनराशि हजार ₹ में)

लेखाशीर्षक	आवंटित धनराशि
2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	
01-वानिकी	
800-अन्य व्यय	
13-वनों की सुरक्षा योजना	
04-यात्रा व्यय	550
15-मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	500
23-गुप्त सेवा व्यय	200
25-लघु निर्माण कार्य	5000
26-मशीन साज-सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र	50
29-अनुरक्षण	500
41-भोजन व्यय	200
42-अन्य व्यय	200
योग	7200

- मानक मद 25-लघु निर्माण कार्य में आवंटित धनराशि से प्रस्तावित प्रत्येक निर्माण कार्य की लागत ₹5.00 लाख से अधिक न हो अर्थात् इस धनराशि से ₹5.00 लाख तक की ही लागत के निर्माण कार्य कराये जाए। सर्वप्रथम गत वर्षों के अवशेष कार्य पूर्ण किये जाय तदोपरांत ही नए कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त की जाय।
- धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं०-400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01.04.15 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि से मात्र योजना से सम्बन्धित कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें एवं ऐसे कार्य न कराए जिन हेतु राज्य सेक्टर में अलग से योजना उपलब्ध हैं, यदि योजना से इतर कार्यों को कराना पाया गया तो इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगा।



.....2

4. कार्यो को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।
5. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।
7. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
8. धनराशि का व्यय दिनांक 31.03.2016 तक सुनिश्चित किया जायेगा यदि उक्त तिथि के पश्चात कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे निमनानुसार राजकोष में समर्पित कर दिया जायेगा।

2- उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या-27 के आयोजनागत पक्ष में उपरोक्त तालिका में वर्णित लेखाशीर्षक की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा। कम्प्युटरीकृत अलोटमेंट आई0डी0-S1602270300 दिनांक 15.02.2016 संलग्न है।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0-400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01.04.2015 एवं शासनादेश संख्या 1386/XXVII(1)/2015 दि0 17.11.2015 के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

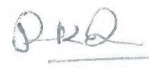
भवदीय,

(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव

संख्या-474/X-2-2016-12(32)/2012 तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अनुभाग-4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
8. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।


(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20152016

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - 474/X-2-2016-12(32)/2012

अनुदान संख्या - 027

अलोटमेंट आई डी - S1602270300

आवंटन पत्र दिनांक -15-Feb-2016

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

- 1: लेखा शीर्षक 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन 01 - वानिकी
800 - अन्य व्यय 13 - वनों की सुरक्षा योजना
00 - वनों की सुरक्षा हेतु अतिक्रमण रोकने के लिये सर्वे/वाउन

Plan Voted			
मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
04 - यात्रा व्यय	550000	550000	1100000
15 - गाड़ियों का अन्तरक्षण और पेट्र	500000	500000	1000000
23 - ग्राम सेवा व्यय	200000	200000	400000
25 - लघु निर्माण कार्य	5000000	5000000	10000000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	50000	50000	100000
29 - अन्तरक्षण	500000	500000	1000000
41 - भोजन व्यय	200000	200000	400000
42 - अन्य व्यय	200000	200000	400000
	7200000	7200000	14400000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

7200000